भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.†5115
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम

†5115. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री कार्तिक चन्द्र पॉल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) राज्यों की सर्वोत्तम खनन पद्धतियों पर व्यापक प्रतिवेदन में सरकार द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;
(ख) हाल ही में शुरू की गई माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम (एमटीएस) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;
(ग) सर्वोत्तम खनन पद्धतियों को अपनाए जाने से लघु और मध्यम स्तर के खनन कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
(घ) इस सम्मेलन से महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान मिलेगा?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) खनन में राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों पर व्यापक रिपोर्ट में राज्यों के बीच पीयर लर्निंग को बढ़ावा देने और खनन क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने हेतु अलग-अलग राज्यों द्वारा खनिज प्रशासन में अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रलेखित किया गया है। गवेषण दक्षता में सुधार, सततता को बढ़ावा देने, विनियमों को सरल बनाने और सामुदायिक लाभ बढ़ाने पर ध्यान देते हुए रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ खनन मंजूरी और अनुमोदन को सुव्यवस्थित करना, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा कोष के साथ गवेषण डेटा का एकीकरण, गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग, तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए राज्य खनन और भूविज्ञान निदेशालयों (डीएमजी) को मजबूत करना, नीलाम किए गए

खनिज ब्लॉकों का संचालन, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए गौण खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) और खनन टेनेमेंट प्रणाली (एमटीएस) को अपनाना तथा प्रतिपूरक वनीकरण की सुविधा के लिए लैंड बैंकों का निर्माण करना शामिल हैं।

(ख) हाल ही में शुरू की गई माइनिंग टेनमेंट प्रणाली (एमटीएस) का मुख्य उद्देश्य खनन से संबंधित प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल करना, पारदर्शिता बढ़ाना, बेहतर डेटा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना, हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना, भावी प्रौद्योगिकी उन्नति को समायोजित करने के लिए एक लचीली प्रणाली प्रदान करना और खनिज संसाधन प्रबंधन की दक्षता में सुधार करना है।

(ग) भारत में सर्वोत्तम खनन पद्धतियों को अपनाकर, छोटे और मध्यम स्तर के खनन प्रचालन अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ा सकते हैं, सततता सुनिश्चित कर सकते हैं और इस प्रकार, खनन क्षेत्र का समग्र विकास कर सकते हैं।

(घ) जनवरी 2025 में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन में खनिज समृद्ध राज्यों के खनन मंत्रियों, उद्योग के अग्रणियों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर मुख्य ध्यान दिया गया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा खनिज गवेषण, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण से लेकर सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। सम्मेलन के दौरान, राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण, खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने, नीलाम की गई खानों के प्रचालन में तेजी लाने, गवेषण डेटा को राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा कोष में एकीकृत करने तथा घरेलू आपूर्ति को मजबूत करने के लिए उद्योगों को विदेशों से महत्वपूर्ण खनिजों को प्राप्त करने और लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सम्मेलन में आठ राज्यों में ग्रेफाइट, टंगस्टन, दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिज सहित 15 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पांचवीं श्रृंखला की नीलामी का शुभारंभ भी हुआ। इन पहलों का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना और उन्हें मजबूत करना तथा महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान देना है।

*****